मैरी

बनाम

केरल राज्य और अन्य

(2003 की सिविल अपील सं.9466)

22 अक्टूबर, 2013

(चंद्रमौली के.आर. प्रसाद और वी.गोपाला गौड़ा, जे.जे.)

केराला अबकारी दुकानें (नीलामी में प्रदर्शन) नियम, 1974:

आरआर। 5 (10), (15) और (19)-नीलामी में असफल खरीदार समझौते को निष्पादित करें-जमा की ज़ब्ती-आयोजितः उप-आर के संदर्भ में (15) आर.5, नीलामी खरीदार द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि जब्त की जा सकती है।

अनुबंध अधिनियम, 1872:

एस.56 - कार्य करने का अनुबंध, बाद में बनने के लिए असंभव-हताशा का सिद्धांत-सांविधिक अनुबंध नीलामी खरीदार को स्थानीय निवासियों के विरोध के कारण अबकारी की दुकानें चलाना असंभव लग रहा है, यह क्षेत्र एक पवित्र स्थान है राज्य ने इसे फिर से बेचना या फिर से निपटाना भी असंभव पाया। अरैक की दुकानें- आयोजितः हताशा के सिद्धांत को बाहर रखा गया है आम तौर पर आगे का प्रदर्शन जहां अनुबंध मौन है

शाब्दिक रूप से असंभव हो रहा है-हालांकि, एक वैधानिक में अनुबंध जिसमें पक्ष पूर्ण जिम्मेदारी लेता है, वह दायित्व से बच नहीं सकता है जो भी कारण हो सकता है। स्थिति, घटनाएँ पक्ष को संविदात्मक दायित्व के गैर-प्रदर्शन के परिणाम से मुक्त नहीं करेंगी इसके अलावा, ऐसे मामले में जिसमें अनुबंध के गैर-निष्पादन का परिणाम वैधानिक अनुबंध में ही प्रदान किया गया है, पक्षकार उससे बाध्य होंगे और अनुबंधों के पीछे शरण नहीं ले सकते हैं। तत्काल मामला, उप-आर के कारण। (15) आर.5 1974 के नियम, राज्य प्रतिभूति धन को ज़ब्त करने का हकदार था-विशिष्ट परिणाम प्रदान किए जाने के बावजूद, अपीलार्थी इसके द्वारा बाध्य होगा और एस का लाभ नहीं उठा सकता है। 56 - केरल अबकारी दुकाने (नीलामी में निपटान) नियम, 1974-- आर। 5 (15) - सिद्धांत/सिद्धांत-हताशा हताशा का सिद्धांत-निष्पक्षता का सिद्धांत।

प्रशासनिक कानूनः

निष्पक्षता का सिद्धांत-आयोजितः यह एक सिद्धांत है जिसमें विकसित किया गया है कानून का शासन सुनिश्चित करने और रोकने के लिए प्रशासनिक कानून क्षेत्र न्याय की विफलता जहां कोई कार्रवाई प्रशासनिक प्रकृति की हो- जहाँ कार्य अर्ध-न्यायिक है, निष्पक्षता का सिद्धांत - निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया गया है, लेकिन निश्चित रूप से इसे किसी स्पष्ट अवधि में संशोधन, परिवर्तन या

परिवर्तन के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। पक्षों के बीच अनुबंध-यह तब भी होता है जब अनुबंध एक वैधानिक प्रावधान-उप-आर द्वारा शासित होता है। (15) आर.5 1974 का नियमों को इस आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता है कि तर्कसंगतता और निष्पक्षता-केरल अबकारी दुकानें (नीलामी में निपटान) नियम, 1974 - आर.5 (15)

अपीलार्थी, एक में सफल बोलीदाता होने के नाते नीलामी दो दुकानों में वेंड अरैक को विशेषाधिकार की बिक्री के लिए आयोजित की गई, बोली राशि का 30 प्रतिशत जमा किया गया और आर के संदर्भ में एक अस्थायी समझौते को निष्पादित किया। 5 (10) में से केरल अबकारी दुकानें (नीलामी में निपटान) नियम, 1974, जो बोर्ड द्वारा पुष्टि के अधीन था राजस्व। क्षेत्र पवित्र स्थान होने के कारण, स्थानीय निवासियों ने किसी भी दुकान को चलाने पर आपत्ति जताई क्षेत्र। बड़ी संख्या में लोगों ने एकत्र किया और पेशकश की आबकारी की दुकानें खोलने के लिए शारीरिक प्रतिरोध और कानून और व्यवस्था लागू करने वाली एजेंसी व्यवसाय के सुचारू संचालन का आश्वासन नहीं दे सकी। हालाँकि, अपीलार्थी था उसके द्वारा देय शेष राशि जमा करने के लिए कहा गया, उस पर 18 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ। राजस्व वसूली के लिए नोटिस भी जारी किया गया था राशि। अपीलार्थी ने एक रिट में नोटिसों को चुनौती दी उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका में तर्क दिया गया है कि आरआर। भारत का संविधान। अपीलार्थी ने अन्य बातों के साथ-साथ राज्य को निर्देश देने का अनुरोध

करते हुए एक और रिट याचिका दायर की प्रारंभिक जमा के रूप में उसके द्वारा भुगतान की गई राशि को वापस करने के लिए अधिकारी। एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिकाओं की अनुमति दी गई और नोटिस और अपीलार्थी के खिलाफ शुरू की गई सभी कार्यवाही को रद्द कर दिया गया। यह राशि ब्याज के साथ। हालांकि, एकल न्यायाधीश ने ऐसा नहीं किया आरआर को नीचे करें। 5 (15) और 5 (16) के रूप में दायर की गई रिट अपील शेष राशि की वसूली के संबंध में था खारिज कर दिया गया जबकि निर्देश के खिलाफ रिट अपील प्रारंभिक जमा राशि की वापसी के लिए अनुमति दी गई थी डिवीजन बेंच।

बोलीदाता द्वारा दायर तत्काल अपील में, अपीलार्थी तर्क दिया, अन्य बातों के साथ, कि आर 5 (15) तर्कसंगतता या निष्पक्षता के सिद्धांत की आवश्यकता को पूरा नहीं किया और केवल इसी आधार पर नियम अमान्य होगा। हालांकि, इस तरह की याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं उठाई गई थी अदालत। निर्णय के उस भाग की वैधता के संबंध में जिसके द्वारा खंड पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि राज्य था पूरी जमा राशि को ज़ब्त करने का हकदार, न्यायालय के समक्ष विचार के लिए प्रश्न थाः क्या अपीलार्थी कुंठा के सिद्धांत का आह्वान कर सकता है या असंभवताया क्या वह शर्तों से बंधी थी वैधानिक अनुबंध।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

1. केरल अबकारी दुकानों का नियम 5 (15) (नीलामी में निपटान) नियम, 1974 यह स्पष्ट करता है कि नीलामी खरीदार के निष्पादन में विफलता पर समझौता चाहे अस्थायी हो या स्थायी, नीलामी खरीदार द्वारा पहले से ही बकाया राशि के लिए जमा की गई राशि धन और प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी। निर्विवाद रूप से, अपीलार्थी को नीलामी घोषित किया गया था खरीदार और वास्तव में, उसने बोली का 30 प्रतिशत जमा किया था। आर के संदर्भ में राशि। 5 (10) नियमों से। यह आगे एक स्वीकृत स्थिति है कि अपीलार्थी ने एक निष्पादन नहीं किया स्थायी समझौते या उस मामले के लिए, विशेषाधिकार का निष्पादन नहीं किया। इसलिए, उप-आर के संदर्भ में। (15) आर.5, उसके द्वारा जमा किया गया पैसा ज़ब्त होने योग्य है। (पैरा 12) (1139 - ई-जी)

2. यह राज्य का मामला नहीं है कि अपीलार्थी ने जानबूझकर, या किसी तिरछे उद्देश्य के लिए, या किसी भी नुकसान से बचने के लिए एक उपकरण के रूप में, समझौते को निष्पादित करने से इनकार कर दिया। यह ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य असहाय था क्योंकि पवित्र स्थान पर अरक की बिक्री के खिलाफ सार्वजनिक विद्रोह जगह। नतीजतन, राज्य ने अरक की दुकानों को फिर से बेचना या फिर से निपटाना भी असंभव पाया। (पैरा 13) (1140 - बी-सी)

एस के दूसरे पैराग्राफ को देखते हुए। 56 में से किसी घटना के कारण अनुबंध किया जाता है जो वादा जो रोक नहीं सका वह असंभव हो जाता है, शून्य हो जाता है। इसलिए, प्रतिभूति की ज़ब्ती राशि अवैध हो सकती है। लेकिन तत्काल मामले में, अनुबंध के गैर-प्रदर्शन का परिणाम है वैधानिक अनुबंध में ही प्रदान किया गया है। हताशा का सिद्धांत सामान्य रूप से आगे के प्रदर्शन को शामिल नहीं करता है जहां निष्पादन के वस्तुतः असंभव होने की स्थिति में पक्षों की स्थिति के बारे में अनुबंध मौन है। हालांकि, एक वैधानिक अनुबंध जिसमें पक्ष लेता है संविदात्मक दायित्व का निष्पादन। इसके अलावा, ऐसे मामले में जिसमें गैर-निष्पादन के परिणाम अनुबंध वैधानिक अनुबंध में ही प्रदान किया गया है, पक्ष उससे बाध्य होंगे और एस के पीछे शरण नहीं ले सकते हैं। 56 अनुबंध अधिनियम। नियम 5 (15) अनिश्चित शर्तें प्रदान करती हैं कि "की विफलता पर में निर्दिष्ट ऐसी जमा राशि करने के लिए नीलामी खरीदार। उप-नियम (10) "या" ऐसे समझौते को अस्थायी या स्थायी रूप से निष्पादित करें ",उसके द्वारा पहले से ही इसके लिए जमा की गई राशि। वास्तविक धन और प्रतिभूति को जब्त कर लिया जाएगा सरकार"। तत्काल मामले में, अपीलार्थी ने उप-आर में दिए गए कई दायित्वों का पालन नहीं किया था। (10) आर.5 और परिणामस्वरूप, उप-आर के कारण। (15), द.राज्य को प्रतिभूति राशि को जब्त करने का अधिकार था। चेहरे पर। प्रदान किए गए विशिष्ट परिणामों में से, अपीलार्थी एस का लाभ नहीं उठा

सका। 56 प्रतिभूति धन की जब्ती का विरोध करने के लिए अनुबंध अधिनियम। (पैरा 13) (1140 - सी-एच; 1141-ए)

सुशीला देवी बनाम हरिसिंह (1971) 2 एससीसी 288; हर प्रसाद चैबे बनाम भारत संघ (1973) 2 एससीसी 746- प्रतिष्ठित।

3. निष्पक्ष रूप से कार्य करने के कर्तव्य को वैधानिक अनुबंध में शामिल करने की मांग की जाती है ताकि बोली को जब्त करने से बचा जा सके। राशि निष्पक्षता का सिद्धांत और कुछ नहीं बल्कि एक कर्तव्य है निष्पक्ष और उचित रूप से कार्य करें। यह कानून के शासन को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक कानून के क्षेत्र में विकसित एक सिद्धांत है और प्रकृति में जहाँ कार्य अर्ध-न्यायिक है, निष्पक्षता का सिद्धांत निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया गया है। लेकिन, निश्चित रूप से इसे पार्टियों के बीच अनुबंध की एक स्पष्ट अवधि में संशोधन, परिवर्तन या परिवर्तन के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। यह है इसलिए भले ही अनुबंध एक वैधानिक द्वारा शासित हो प्रावधान अर्थात जहाँ यह एक सांविधिक अनुबंध है। एक अनुबंध में बकारी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत, अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम और उसके तहत बना गए नियमों के नियमों और शर्तों का पालन करने का वचन देता है जो हैं -वैधानिक और ऐसी स्थिति में, लाइसेंस धारी

निष्पक्षता या तर्कसंगतता के सिद्धांत का आह्वान नहीं कर सकता है। (पैरा 18 और 20) (1144-डी-ई; 1146-बी-सी)

दिल्ली परिवहन निगम बनाम डी.टी.सी. मजदूर कांग्रेस और एक अन्य 1990 (1) पूरक। एस.सी.आर.142= 1991 पूरक (1) एस.सी.सी.600; और केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड और एक अन्य वी। ब्रोजो नाथ गांगुली और एक अन्य आदि। 1986 (2) एस.सी.आर.278 = (1986) 3 एस.सी.सी.156-संदर्भित।

इसलिए, यह न्यायालय मानता है कि आर। 5 (15) नियमों में से अपीलार्थी और एक सांविधिक अनुबंध को निष्पक्षता के सिद्धांत को लागू करके बदला, जोड़ा या बदला नहीं जा सकता है। इस तरह के अनुबंध में, लाइसेंसधारी एक परिकलित जोखिम लेता है। अपीलार्थी अनुबंध के तहत उसके द्वारा किए गए दायित्वों से मुक्त नहीं किया जा सकता है। (पैरा 18) (1144-जी-एच)

सहायक आबकारी आयुक्त और अन्य बनाम आइज़ैक पीटर और अन्य =1994 (2) एससीआर 67 =(1994) 4 एससीसी 104-निर्भर पर।

मामला कानून संदर्भः

(1971)2 एससीसी 288 प्रतिष्ठित पैरा 8

(1973) 2 एस.सी.सी.746 प्रतिष्ठित पैरा 9

1986 (2) एससीआर 278 संदर्भित किया गया है पैरा 15

1990 (1) पूरक एस.सी.आर.142 को संदर्भित किया गया पैरा 17

1994 (2) एससीआर 67 उस पर भरोसा करें

निर्णय व आदेश दिनांक 16.06.2022 डब्ल्यू ए नम्बर 1374/1994 उच्च न्यायालय केरला अर्णाकुलम

नेहा अग्रवाल, श्याम डी.नंदन, सुब्रमण्यम प्रसाद अपीलार्थी के लिए।

मुक्ति चैधरी, रमेश बाबू एम.आर., जी.प्रकाश उत्तरदाता।

न्यायालय का निर्णय जस्टिस के द्वारा चंद्रमौली के.आर.प्रसाद, जे किया गया था।

1. अपीलार्थी केरल उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 13.06.2002 रिट अपील अपील नम्बर 1374/1995 से व्यथीत होकर न्यायालय के समक्ष आज्ञा हेतु उपस्थित हुआ है, जहां पर उक्त न्यायालय द्वारा एकल जज उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04.08.1995 जो कि ऑरिजनल पीटिशन नम्बर 12514/1994 में अपीलार्थी को रिफन्ड हेतु रूपये 7,68,600/-रूपये।

2. अपीलार्थी, मैरी को अरक की बिक्री के लिए विशेषाधिकार दिनांक 24.03.1994 को आयोजित निलामी में दुकान नम्बर 47 से 55 व 55 कालाडी रैंज 3 अवधि 1.4.1994 से 31.3.1995 तक बोली से हासिल हुये। उसकी बोली 25,62,000/-रूपये की थी वेंड अरैक के विशेषाधिकार की बिक्री केरल आबकारी दुकानें (नीलामी में निपटान) नियम, 1974

(इसके बाद 'नियम' के रूप में संदर्भित) द्वारा शासित है। अधिकारी ने बिक्री के संचालन ने अपीलार्थी को नियमों के नियम 5 (8) के संदर्भ में 'नीलामी खरीदार' घोषित किया। घोषित नीलामी खरीदार के रूप में, उन्होंने बोली राशि का 30 प्रतिशत जमा किया अर्थात् उसी तारीख को रु.7,68,600/- और नियम 5 (10) के संदर्भ में एक अस्थायी समझौते को निष्पादित किया जो राजस्व बोर्ड द्वारा पुष्टि के अधीन था। नियम 5 (19) इस जमा को शर्तों के उचित लाइसेंस प्रदर्शन के लिए प्रतिभूति बनाता है। कालाडी आदि शंकराचार्य का पवित्र जन्म स्थान है और इसके बगल में सेंट थॉमस से जुड़ा एक ईसाई तीर्थस्थल था। उन क्षेत्रों के निवासियों ने किसी भी अबकारी की दुकान का संचालन का विरोध किया। बड़ी संख्या में एकत्र हुए लोग और आबकारी की दुकानों को न खोलने के लिए शारीरिक प्रतिरोध की पेशकश की और कानून और व्यवस्था लागू करने वाली एजेंसी व्यवसाय का सुचारू संचालन करने का आश्वासन नहीं दे सकी। उपरोक्त परिस्थितियों में अपीलार्थी को यह विश्वास करने के लिए मजबूर कर दिया कि उसके लिये विचाराधीन इलाके में अरैक की दुकान चलाना असंभव था। अतः अपीलार्थी द्वारा अपने पत्र दिनांकित 03.04.1994 से राजस्व बोर्ड, जिला कलेक्टर और सहायक उत्पाद शुल्क आयुक्त को संबोधित कर सूचित किया कि जन आंदोलन के कारण उसके लिए दुकानें खोलना और चलाना संभव नहीं था। तदनुसार, उसने उनसे अनुरोध किया कि वे उसके पक्ष में बिक्री की पुष्टि न करें क्योंकि उसके लिए अपने नियंत्रण से बाहर के कारणों से विशेषाधिकार

को निष्पादित करना असंभव था। उसने यह भी अनुरोध किया कि प्रस्तावित अनुबंध को निरस्त माना जा सकता है। परन्तु उसने आगे अपने प्रतिभूति राशि को वापसी का दावा करने का अधिकार को आरक्षित किया। अभिलेख पर यह दिखाने के लिए कोई भी दस्तावेज नहीं है कि अपीलार्थी द्वारा कार्रवाई करने से इनकार करने के बाद अपने दायित्वों के अनुसार, राज्य सरकार ने अरक की दुकानों को फिर से बेचने या फिर से निपटाने के लिए कोई भी कदम उठाया।

3. इसके बावजूद, कालाडी के आबकारी निरीक्षक रेंज ने अन्य बातों के साथ-साथ यह कहते हुए कि बिक्री की पुष्टि पहले ही उसके पक्ष में हो चुकी है अपीलार्थी को दिनांकित 08.04.1994 को एक नोटिस भेजा। अपीलार्थी को पुष्टिकरण सूचना स्वीकार करने के लिए कहा गया और एक स्थायी समझौता करने के लिए कहा गया। उक्त नोटिस के द्वारा आबकारी निरीक्षक ने अपीलार्थी से कारण बताने के लिए भी कहाकि क्यों ना उसके खिलाफ कार्रवाई नियमों के तहत आगे की कार्यवाही की जाये। अपीलार्थी ने अपना जवाब दिनांक 7.4.1994 के द्वारा अरैक की दुकानों को चलाने में अपनी असमर्थता को दोहराते हुए कहा कि उसके खिलाफ आगे सभी कार्यवाही का अनुरोध किया व दिनांक 04.03.1994 पर आयोजित नीलामी के अनुसार रद्द किया जाए और उसके द्वारा पहले से जमा की गई राशि उसे वापस कर दी जाए। ऐसा लगता है कि अपीलार्थी द्वारा दिखाए गए कारण को प्राधिकरण का समर्थन नहीं मिला और सहायक उत्पाद शुल्क आयुक्त ने

दिनांक 20.4.1995 के नोटिस द्वारा अपीलार्थी से राशि का भुगतान करने का आह्वान किया कि उसके द्वारा देय शेष राशि 33,41,400/-रूपये के लिए, उस पर 18 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ। वसूली के लिए दिनांक 30.6.1995 का राजस्व वसूली नोटिस भी जारी किया गया था। उपरोक्त राशि में से अपीलार्थी ने उपरोक्त को चुनौती दी केरल के समक्ष दायर एक रिट याचिका में उन्हें जारी किए गए नोटिस उच्च न्यायालय जो मूल याचिका छव.9976 के रूप में पंजीकृत था 95 का (मैरी बनाम केरल राज्य और अन्य)। उपरोक्त नोटिसों और आगे की कार्यवाही को चुनौती देते हुए, अपीलार्थी उन्होंने तर्क दिया कि नियम 5 (15) और 5 (16) मनमाने हैं और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं। याचिकाकर्ता ने दायर किया एक अन्य रिट याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य के अधिकारियों को प्रारंभिक जमा के रूप में उनके द्वारा भुगतान की गई रुपये की राशि वापस करने का निर्देश देने का अनुरोध करती है। यह रिट याचिका मूल के रूप में दर्ज की गई थी 994 की याचिका सं.12514 (मैरी बनाम केरल राज्य और अन्य)

4. दोनों रिट याचिकाओं की एक साथ सुनवाई की गई और विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 4.8.1995 के फैसले के माध्यम से 1134 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्टों की अनुमति दी। दोनों रिट याचिकाएँ विद्वान एकल न्यायाधीश ने नोटिसों और अपीलार्थी के खिलाफ शुरू की गई सभी कार्यवाही को रद्द कर दिया और आगे ब्याज के साथ उसके द्वारा जमा की

गई रुपये की राशि वापस करने का निर्देश दिया। हालांकि, एकल पीठ न्यायाधीश ने नियम 5 (15) और 5 (16) को निरस्त नहीं किया। ऐसा करते समय, विद्वान एकल न्यायाधीश ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

"15. ऊपर दिए गए निर्विवाद और अनियंत्रित तथ्य स्पष्ट रूप से हताशा के सिद्धांत को आकर्षित करते हैं और असंभवता इस निष्कर्ष की ओर ले जाती है कि अनुबंध इसकी शुरुआत से ही यह शून्य और निष्क्रिय हो जाता है। नतीजतन, इस पर विचार करने और अन्य निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है प्रत्यायोजित की गई ज्यादतियों के संबंध में आग्रह किए गए विवाद नियमों के रूप में कानून, जैसा कि वे हैं उपरोक्त निष्कर्ष को देखते हुए यह पूरी तरह से अनावश्यक है। ये दोनों याचिकाएं तदनुसार सफल होती हैं।

5. केरल राज्य और उसके पदाधिकारी, द्वारा व्यथित उपरोक्त निर्णय ने अलग-अलग अपीलों को प्राथमिकता दी। दोनों अपीलों को एक साथ सुना गया और एक निर्णय द्वारा निपटाया गया। 1995 की रिट अपील संख्या 1722, के खिलाफ दायर की गई शेष राशि की वसूली को खारिज कर दिया गया। 1995 की रिट अपील संख्या 1734 को अनुमति देते हुए जो निर्देश के खिलाफ थी प्रारंभिक जमा राशि की वापसी के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश की, खंड पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि राज्य को जब्त

करने में न्यायसंगत है नियम 5 (15) को ध्यान में रखते हुए उक्त राशि। ऐसा करते हुए, प्रभाग पीठ ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

"8 .....हालांकि, जहां वैधानिक प्रावधान हैं, अनुबंध की शर्तों को वैधानिक प्रावधानों द्वारा परिभाषित किया जाता है। जिसे पक्षों के बीच संबंधों को नियंत्रित करना चाहिए। जहां कानून संबंधों को नियंत्रित करता है, यह वैधानिक शर्तें हैं जिन्हें दलों के बीच विवादों को तय करने के लिए लागू किया जाना है। इस मामले में, विशेष रूप से जब विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा नियम 5 के उप-नियम (15) और (16) की अयोग्यता के तर्क को अस्वीकार कर दिया गया था, तो हम उनका विचार है कि अधिकारों और देन दारियों के बीच पार्टियों को विशुद्ध रूप से लागू नियम के अनुसार काम करना होगा।

6. तदनुसार, खंड पीठ ने पाया कि अपीलार्थी के स्वीकार किए जाने के बाद, उसे वापस नहीं लिया जा सकता था। उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, उच्च न्यायालय ने नियम 5 के उप-नियमों (10) और (15) पर निर्भरता रखी और निम्नलिखित रूप में देखा गयाः

नियम 5 के उप-नियम (10) के तहत प्रावधानों से स्पष्ट है इसलिए, प्रथम प्रत्यर्थी प्रस्ताव को वापस लेने या दिनांकित पत्र द्वारा अनुबंध को रद्द करने का इरादा नहीं रख सकता था। 3.4.1994 यह भी कि पहले प्रत्यर्थी ने नियम 5 के उप-नियम (10) में दिए गए कई दायित्वों का पालन नहीं

किया रुपये की पूरी जमा राशि 7,68,600/- अब तक वहाँ है कोई कठिनाई नहीं।

7. वर्तमान अपील में, हमें निर्णय के इस भाग की वैधता की जांच करने के लिए कहा गया है जिसके द्वारा -डिवीजन बेंच ने माना कि राज्य को ज़ब्त करने का अधिकार है राशि 7,68,600/-रुपये की पूरी जमा राशि।

8. हमने अपीलार्थी के लिए सुश्री नेहा अग्रवाल को सुना है और उत्तरदाताओं के लिए सुश्री मुक्ता चौधरी। सुश्री अग्रवाल का तर्क है कि अपीलार्थी अपने दायित्व का पालन नहीं कर सकी जैसा कि जन आंदोलन को देखते हुए यह असंभव हो गया और प्रतिरोध जिसे राज्य नियंत्रित नहीं कर सका। इस संबंध में उन्होंने अनुबंध अधिनियम की धारा 56 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। सुशीला देवी बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर समर्पण निर्भरता का समर्थन भी रखा गया है। हरि इंग, (1971) 2 एस.सी.सी.288, और हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है। निर्णय का अनुच्छेद 11 जो इस प्रकार हैः

"11.हमारी राय में इस बिंदु पर निष्कर्ष अपीलीय न्यायालय टिकाऊ नहीं है। लेकिन वास्तव में, जैसा कि निचली अदालत के साथ-साथ अपीलीय अदालत ने पाया, यह था वादी के लिए पाकिस्तान में प्रवेश करना भी असंभव है। दोनों ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ अपीलीय अदालत ने पाया है कि मौजूदा परिस्थितियों के कारण, यह था दी के लिए या तो

कब्जा करना असंभव है पट्टे पर दी जाने वाली या यहाँ तक कि किराया लेने के लिए भी संपत्तियाँ किसानों से। उस स्थिति के लिए वादी किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं थे। जैसा कि इस न्यायालय ने कहा है कि सत्यब्रत घोष बनाम मुगनीराम बांगुर एंड कंपनी, (1954) एस.सी.आर 310, हताशा का सिद्धांत वास्तव में एक पहलू है या कारण से अनुबंध के निर्वहन के कानून का हिस्सा अधिनियम की असंभवता या अवैधता का पर्यवेक्षण करना और इसलिए यह धारा के दायरे में आता है। 56 भारतीय अनुबंध अधिनियम। यह दृष्टिकोण कि धारा 56 केवल भौतिक असंभवता के मामलों पर लागू होता है और वह जहां यह धारा लागू नहीं है, वहां इसका सहारा लिया जा सकता है। कुंठा के विषय पर अंग्रेजी कानून के सिद्धांतों के लिए सही नहीं है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 56 में कहा गया है सकारात्मक कानून का एक नियम नीचे और मामले को नहीं छोड़ता हैपक्षकारों के इरादे के अनुसार निर्धारित किया जाना। धारा 56 द्वारा परिकल्पित असंभवता अनुबंध अधिनियम किसी ऐसी चीज तक सीमित नहीं है जो नहीं है मानवीय संभव। यदि एक अनुबंध का प्रदर्शन पक्षों के उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अव्यावहारिक या बेकार हो जाता है तो यह होना चाहिए माना कि अनुबंध का प्रदर्शन हो गया है असंभव है। लेकिन पर्यवेक्षण घटनाओं को अनुबंध के आधार को छीन लेना चाहिए और यह इस तरह का होना चाहिए कि यह अनुबंध की जड़ पर प्रहार करे।

9. एक और निर्णय जिस पर सुश्री अग्रवाल ने निर्णय लिया है हर प्रसाद चैबे मामले में इस अदालत का फैसला है भारत संघ, (1973) 2 एस.सी.सी.746, पैराग्राफ 9 में निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया हैः

> "9.इस विस्तृत वर्णन से यह स्पष्ट हो जाएगा कि अपीलार्थी ने ईमानदारी से कोयले के लिए बोली लगाई थी और उचित धारणा है कि उसे अनुमति दी जाएगी यले को फिरोजाबाद ले जाएँ, कि इसे विफल कर दिया गया था कोयला आयुक्त का रवैया, कि बाद में पार्टियां इस आधार पर आगे बढ़ीं कि नीलामी बिक्री थी रद्द किया जाना और अपीलार्थी ने अपना पैसा वापस कर दिया। लेकिन जाहिरा तौर पर क्योंकि उस समय तक अधिकांश कोयला था खो गया और रेलवे मुश्किल में पड़ गया होगा हम इस तरह के इनकार के लिए तथ्यों पर कोई औचित्य नहीं देख सकते हैं और प्रतिवादी वादी के पैसे वापस करने से इनकार नहीं कर सकते हैं। राशि अनुबंध स्पष्ट रूप से निराशाजनक हो गया था। हम यह स्पष्ट करना चाहिए कि हम इनकार का जिक्र नहीं कर रहे हैं वैगनों की आपूर्ति करने के लिए लेकिन कोयले से इनकार आयुक्त कोयले की आवाजाही की अनुमति देने के लिए फिरोजाबाद इस तथ्य के बावजूद कि

यह एक नहीं था नीलामी की शर्तें। इसलिए, अपीलार्थी स्पष्ट रूप से है अपने धन की वापसी का हकदार है। इसके अलावा, अनुबंध स्वयं धारा 175 के अनुसार नहीं है भारत सरकार अधिनियम अमान्य है और अपीलार्थी है पने धन की वापसी का हकदार है। हम असमर्थ हैं उच्च न्यायालय के तर्क को समझें जब वह आय जैसे कि अपीलार्थी को लागू करने की कोशिश कर रहा था अनुबंध। हम निचली अदालत के लिए कोई औचित्य नहीं देख सकते हैं। कम से कम वादी की राशि पर ब्याज देने से इनकार करना उसकी मांग की तारीख से, या की तारीख से नवीनतम सूट"

10. सुश्री चौधरी, हालांकि, तर्क देती हैं कि मामले में हाथ, विशेषाधिकार प्रदान करने के लिए नियम और शर्तें शासित हैं नियमों द्वारा और प्रदान किए गए विशिष्ट परिणामों को देखते हुए या अनुबंध के नियमों और शर्तों का गैर-अनुपालन. ई. प्रतिभूति धन की जब्ती करते हुए, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने यह अभिनिर्धारित करने में कोई त्रुटि नहीं की है कि राज्य वह पूरी जमा राशि को ज़ब्त करने का हकदार था।

11. प्रतिद्वंद्वी के समर्पण को देखते हुए हम इसे समीचीन समझते हैं प्रासंगिक नियमों से गुजरना। नियम 2 (ए) आबकारी दुकान को परिभाषित करता है। एक अरैक की दुकान को शामिल करना

जिसके साथ हम वर्तमान अपील में चिंतित हैं। नियमों के अध्याय प्ट में सामान्य प्रावधान हैं - आबकारी दुकानों की बिक्री के लिए लागू शर्तें। इसमें केवल एक नियम अर्थात नियम 5 लेकिन इसमें 22 उप-नियम हैं। नियम का उप-नियम 15 5 इस प्रकार पढ़ता हैः

(15) शोधन क्षमता प्रमाण पत्र और नकद प्रतिभूति के अलावा उप-नियम (10) में उल्लिखित नीलामी खरीदार ऐसी व्यक्तिगत प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत करें जो उससे अपेक्षित हों। सहायक आबकारी आयुक्त की संतुष्टि के लिए। आवश्यक है, नीलामी खरीदार को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है अतिरिक्त नकद प्रतिभूति जो उनके द्वारा निर्धारित की जा सकती है पुष्टि का समय। नीलामी खरीदार भी इन नियमों के साथ जोड़ा जाता है और आवश्यक लाइसेंस लेता है। दुकान या दुकानों की स्थापना से पहले। की विफलता पर नीलामी खरीदार ऐसी जमा राशि जमा करने के लिए अस्थायी या स्थायी समझौता या ऐसा प्रदान करना व्यक्तिगत प्रतिभूति या अतिरिक्त नकद प्रतिभूति जैसा कि ऊपर कहा गया है। बकाया राशि के लिए उसके द्वारा पहले से की गई जमा राशि और सरकार और दुकान की प्रतिभूति जब्त कर ली जाएगी। सहायक उत्पाद शुल्क द्वारा पुनर्विक्रय या अन्यथा निपटान बोर्ड द्वारा पुष्टि के अधीन आयुक्त राजस्व। अन्यथा निपटान में बंद करना शामिल है या विभागीय प्रबंधन। एक की मृत्यु के मामले में स्थायी के निष्पादन से पहले नीलामी खरीदारसमझौता, वही के उत्तराधिकारियों से प्राप्त किया जाएगा मृतक जब तक सहायक आबकारी

आयुक्त न हो राजस्व बोर्ड द्वारा पुष्टि के अधीन अनुबंध रद्द करें। नीलामी की मृत्यु के मामले में दुकान की बिक्री की पुष्टि के बाद खरीदार या दुकानों, उसके उत्तराधिकारियों, यदि कोई हो, को उत्पादन करने की आवश्यकता होगी के दावे के समर्थन में आवश्यक कानूनी साक्ष्य और उसी का उत्पादन दुकान को हस्तांतरित किया जाएगा उन्हें और इस तरह के हस्तांतरण के लंबित होने पर दुकान चलाई जाएगी विभागीय प्रबंधन। यह सहायक के लिए खुला है। आबकारी आयुक्त उन्हें प्रस्तुत करने के लिए बुलाएंगे अतिरिक्त सुरक्षा, यदि उनकी राय में यह आवश्यक है अनुबंध का सफल संचालन। यदि उत्तराधिकारी असफल हो जाते हैं की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर उत्पादन नीलामी खरीदार की मृत्यु में आवश्यक साक्ष्य उनके दावे का समर्थन या अतिरिक्त प्रतिभूति जमा करने के लिए आवश्यक, सहायक उत्पाद शुल्क आयुक्त आदेश देगा दुकान या दुकानों की पुनः बिक्री या अन्यथा निपटान मूल खरीदार के जोखिम पर दुकान या दुकानें राजस्व बोर्ड द्वारा पुष्टि के अधीन।

(हमारा रेखांकित करना)

12. उपरोक्त प्रावधान के एक सादे पठन से यह है - स्पष्ट है कि नीलामी खरीदार के निष्पादित करने में विफलता पर समझौता चाहे अस्थायी हो या स्थायी, नीलामी खरीदार द्वारा दी गई राशि याप्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी। निर्विवाद रूप से, अपीलार्थी नीलामी

खरीदार घोषित किया गया था और वास्तव में, बोली राशि का 30 प्रतिशत जमा किया गया, अर्थात 7,68,600/- नियम 5 (10) के अनुसार जमा किये। यह एक स्वीकृत स्थिति है कि अपीलार्थी ने किसी स्थायी समझौते का निष्पादन नहीं किया या उस मामले के लिए विशेषाधिकार का निष्पादन नहीं किया। इसलिए, उप नियम 5 के नियम (15) के अनुसार, उसके द्वारा जमा किया गया धन जब्त किया जा सकता है। हालाँकि, अपीलार्थी द्वारा यह कहा गया है कि उसके नियंत्रण से परे तथ्यों के कारण वह उसे दिए गए विशेषाधिकार से लाभ प्राप्त करने में असमर्थ रही और इसलिए दुकान नहीं चलाई। इसलिए, उसके द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि ज़ब्त होने के योग्य नहीं है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, क्या अपीलार्थी हताशा या असंभवता का सिद्धांत का आह्वान कर सकती है। या क्या वह वैधानिक अनुबंध की शर्तों से बाध्य होगी। दूसरे शब्दों में, एक सांविधिक अनुबंध के मामले में, क्या यह आवश्यक रूप से एक सामान्य अनुबंध की सभी घटनाओं को नष्ट कर देगा जो अन्यथा शासित हैं अनुबंध अधिनियम द्वारा?

13. यह राज्य का मामला नहीं है कि अपीलार्थी ने जानबूझकर, या किसी तिरछे उद्देश्य के लिए, या किसी नुक्सान से बचने के लिए समझौते को निष्पादित करने से इनकार कर दिया। हमें ऐसा लगता है कि सार्वजनिक उथल-पुथल के कारण व आदि शंकराचार्य के जन्म स्थान कलाडी में अरक की बिक्री के खिलाफ उसकी जन्म भूमि को अपवित्र किये

जाने के कारण राज्य असहाय था।नतीजतन, राज्य ने यह भी असंभव पाया कि अरैक की दुकानों को फिर से बेचें या उनका फिर से निपटान करें। दूसरी ओर अनुबंध अधिनियम की धारा 56 का अनुच्छेद, एक ऐसा कार्य करने का अनुबंध जो अनुबंध के बाद किया जाता है, कुछ कारणों से ऐसी घटना जिसे वचनदाता रोक नहीं सका असंभव, शून्य प्रस्तुत किया जाता है। अतः, का ज़ब्त करना प्रतिभूति राशि अवैध हो सकती है। लेकिन स्थिति क्या होगी? सामान्य रूप से आगे के प्रदर्शन को शामिल नहीं करता है जहां अनुबंध है की स्थिति में पक्षों की स्थिति के बारे में चुप रहें प्रदर्शन सचमुच असंभव हो रहा है। लेकिन हमारे राय, एक वैधानिक अनुबंध जिसमें पार्टी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी लेती है व दायित्व से बच नहीं सकती जिसका कारण कुछ भी हो सकता है।ऐसी स्थिति में आयोजनों से पार्टी का निर्वहन नहीं होगा संविदात्मक दायित्व के गैर-निष्पादन के परिणाम सेः इसके अलावा, एक मामले में जिसमें गैर के परिणाम अनुबंध का प्रदर्शन वैधानिक अनुबंध में प्रदान किया गया है स्वयं, पक्ष उससे बाध्य होंगे और अनुबंध अधिनियम की धारा 56 के पीछे शरण नहीं ले सकते हैं। नियम 5 (15) अनिश्चित शर्तों में कहा गया है कि "नीलामी की विफलता पर उप-नियम 10 में निर्दिष्ट ऐसी जमा करने के लिए खरीदार या ऐसे समझौते को अस्थायी या स्थायी रूप से निष्पादित करने के लिए उसके द्वारा पहले से ही बकाया धन और प्रतिभूति के लिए किया गया सरकार के हवाले को दिया जाएगा। जब हम उपरोक्त सिद्धांत को

लागू करते हैं तो हम पाते हैं कि अपीलार्थी ने कई कार्यों को पूरा नहीं किया था।नियम 5 के उप-नियम (10) में दिए गए दायित्व और नतीजतन, उप-नियम (15) के कारण, राज्य प्रतिभूति धन को जब्त करने का हकदार था।

14. अब सुशीला देवी (उपरोक्त) और हरप्रसाद चौबे के मामलों में इस न्यायालय के फैसलों पर लौटते हुए(ऊपर), हमारी राय है वे स्पष्ट रूप से हैं अलग करने योग्य है। उन मामलों में अनुबंध में स्वयं इसके गैर-प्रदर्शन के परिणामों के लिए प्रावधान नहीं किया था। उसी तरह, हताशा के सिद्धांत पर भरोसा करते हुए, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए कि पक्ष उत्तरदायी नहीं होंगे। जैसा कि पहले कहा गया है, विशिष्ट परिणामों के बावजूद अपीलार्थी इसके लिए बाध्य होगा व प्रतिभूति धन की जब्ती का विरोध करने के लिए अनुबंध अधिनियम की धारा 56 का लाभ नहीं दिया जा सकता है।

15. इसके विरूद्ध सुश्री अग्रवाल ने नियम 5 (15) की वैधता का मुद्दा उठाया। विद्वान एकल न्यायाधीश में अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका को मंजूर करते हुये व इनके द्वारा नियम 5 (15) और 5 (16) की वैधता की चुनौती को नकार दिया। राज्य द्वारा प्रस्तुत याचिका में ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि अपीलार्थी ने नियमों की अयोग्यता की याचिका उठाई थी, लेकिन हमारे समक्ष अपीलार्थी का तर्क है कि नियम 5 (15) तर्कसंगतता

या निष्पक्षता के सिद्धांत को पूरा नहीं करता है और केवल इस आधार पर नियम अमान्य है। परिणाम स्वरूप, ज़ब्त करना अवैध है। यह इंगित किया गया है कि एक वर्तमान प्रकृति के अनुबंध में अनुबंध करने वाले पक्षों की सापेक्ष सौदेबाजी की शक्ति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसी दृष्टिकोण से विद्वान वकील का तर्क है नियम सार्वजनिक नीति के खिलाफ है। इस संबंध में इस न्यायालय के निर्णय केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड और एक अन्य बनाम ब्रोजो नाथ गांगुली और अन्य (1986) 3 एस.सी.सी.156 से संदर्भ लिया गया है। इस मामले में, स्थायी कर्मचारियों की सेवा की समाप्ति के लिए प्रदान किए गए रोजगार अनुबंध के साथ-साथ सेवा नियमों में भी शर्तें में तीन महीने के नोटिस या भुगतान पर कोई कारण बताए बिना। कर्मचारी, अनुबंध में अवधि और नियमों को आयोजित किया गया था अनुचित, अनुचित, अनुचित और सार्वजनिक नीति के खिलाफ होना। इन आधारों पर इस न्यायालय ने समाप्ति को शून्य कर दिया। फैसले का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः

> "100 .....उक्त नियम निगम और उसके कर्मचारियों के बीच अनुबंध का हिस्सा हैं व कर्मचारी जो मजदूर नहीं हैं। इन कर्मचारियों के पास किसी श्रमिक संघ की शक्ति उनके समर्थन के लिए नहीं थी। उक्त नियमों को तैयार करने में उनकी कोई सहमति नहीं थी। उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था उक्त नियमों को उनके अनुबंध के

हिस्से के रूप में स्वीकार करें। यह गहरा मतभेद था। निगम और उसके कर्मचारी, चाहे वे कर्मचारी हों या अधिकारी निगम एक अधिकारी की सेवाएँ समाप्त करने का खर्च उठा सकता है। यह सैकड़ों अन्य लोगों को पाएगा उसकी जगह ले लेकिन एक अधिकारी अपनी नौकरी खोने का जोखिम नहीं उठा सकता क्योंकि अगर वह ऐसा करता है, तो सैकड़ों नौकरियां उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रही हैं। नियम 9 के खंड (प) जैसा खंड अधिकार और कारण के खिलाफ है। यह पूरी तरह से अनुचित है। इसमें है उन दलों के बीच प्रवेश किया गया जिनके बीच सौदेबाजी की शक्ति की भारी असमानता है। नियम 9 (प) एक शब्द है। निगम और उसके सभी अधिकारियों के बीच अनुबंध। यह बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करता है और यह पूरी तरह से गिर जाता है।ऊपर हमारे द्वारा तैयार किए गए सिद्धांत के भीतर। कई वैधानिक प्राधिकरणों के पास नियम 9 (प) के समान एक खंड है। उनके रोजगार के अनुबंध। जैसा कि सामने आया है। निश्चित मामलों में, पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड और एयर इंडिया इंटरनेशनल के पास यह मामला है। कई सरकारें निगम के अलावा कंपनियाँ (जो पहली है) हमारे सामने अपीलार्थी) के पास यह होना चाहिए। 970 सरकारी

कंपनियां हैं जिनकी चुकता पूंजी 16,414.9/-रूपये है। अभिकरण आ उपकरण सभसँ पैघ अछि। देश में नियोक्ता। 1143 में नियम 9 (प) जैसा खंड के बड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले रोजगार का अनुबंध जनता इसके लिए हानिकारक और जनहित के लिए हानिकारक है यह उन लोगों के मन में असुरक्षा की भावना पैदा करता है जिन पर यह लागू होता है और परिणामस्वरूप यह जनता के खिलाफ है अच्छा है। अतः ऐसा खंड सार्वजनिक नीति का विरोध करता है और सार्वजनिक नीति का विरोध करता है, इसलिए इसके तहत यह अमान्य है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 23।"

16. इस संदर्भ में संवैधानिक बेंच के आदेश जो कि दिल्ली परिवहन निगम बनाम डी.टी.सी.मजदूर कांग्रेस व अन्य और 1991 पूरक (1) एस.सी.सी.600 का भी उल्लेख किया गया है। इस मामले में, ब्रोजो नाथ गांगुली (ऊपर)के मामले की विस्तृत रूप से चर्चा की गई है और बहुमत से विचार का समर्थन करते हुए इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया हैः

"338.तदनुसार मेरा मानना है कि ब्रोजो नाथ गांगुली मामला, (1986) 3 एस.सी.सी.156 को सही ढंग से निर्णित

कियागया था और पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है व और मामले ऊपर दिए गए कानून के आलोक में निर्णित किये जाने चाहिए। रौशनी से जिस मार्ग पर मैं चलता हूँ, उस पर चलते हुए मैं अपने विद्वान भाई, माननीय प्रमुख से सहमत होने में असमर्थता के लिए अपना गहरा खेद व्यक्त करताहूँ। नीचे पढ़ने के सिद्धांत की प्रयोज्यता पर न्याय उल्लंघनकारी प्रावधानों को बनाए रखने के लिए। मैं अपने भाइयों बी.सी.रे व पी.बी.सावंत जस्टिस से सहमत हूँ। उनके तर्क और जो मैंने पहले रखा है, उसके अलावा निष्कर्ष।"

17. हालांकि, यह राज्य प्रत्यर्थी का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील द्वारा तर्क दिया गया है कि तर्कसंगतता या निष्पक्षता का सिद्धान्त वैधानिक अनुबन्धों पर लागू नहीं है। इस न्यायालय के फैसले सहायक आबकारी आयुक्त व अन्य बनाम आइज़ैक पीटर व अन्य(1994) 4 एस.सी.सी.104 पर मजबूत निर्भरता रखते हुये हमारा ध्यान निम्नलिखित अंश की ओर आकर्षित किया गया है-

26 .....अतः हमारा मत है कि - राज्य के साथ स्वतंत्र रूप से किए गए अनुबंधों के मामले में, वर्तमान की तरह एक पार्टी के पक्ष में तर्कसंगतता या निष्पक्षता के सिद्धांत को परिवर्तन या जोड़ने के उद्देश्य से अनुबंध के नियम और शर्तें, केवल इसलिए कि यह राज्यके साथ है,

लागू करने के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे मामलों में, पक्षों के पारस्परिक अधिकार और देनदारियां अनुबन्ध की शर्तों द्वारा शासित होती हैं (जो कुछ मामलों में वैधानिक हो सकते हैं) और अनुबंधों से संबंधित कानूनसे चलती है। यह याद रखना चाहिए कि ये अनुबंध सार्वजनिक नीलामी, टेंडर व बातचीत के अनुसार किये जाते हैं। इन अनुबंधों में प्रवेश करने के लिए किसी को भी मजबूर नहीं किया जाता। ये दोनों तरफ से स्वैच्छिक होते हैं। ऐसे अनुबन्धों में राज्य शक्तियों का उपयोग किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

18. हमने विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को ध्यान से अवलोकन किया परन्तु हम विद्वान अधिवक्ता के इन तर्कों में अपीलार्थी की ओर से व उसके द्वारा दिये गये निर्णयों को देखे तो वाणिज्यिक लेन-देन के मामलों में भिन्नता पाई है। वैधानिक अनुबंधों के मामलों में दी गई राशि से जब्त किये जाने से बचने के लिए निषपक्षता से कार्य करना जरूरी है। निष्पक्षता का सिद्धांत और कुछ नहीं बल्कि निष्पक्ष और यथोचित रूप से कार्य करने का कर्तव्य है। यह कानून के शासन को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक कानून के क्षेत्र में विकसित एक सिद्धांत है और न्याय की विफलता को रोकें जहाँ कोई कार्रवाई प्रशासनिक प्रकृति की है। जहाँ कार्य अर्ध-न्यायिक है, निष्पक्षता का सिद्धांत निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया गया है। लेकिन हमारी राय में, यह निश्चित रूप से यह एक एक्प्रेस अनुबंध को संशोधित करने या बदलने के लिए लागू नहीं

किया जा सकता है। यह तब भी है जब अनुबंध एक वैधानिक प्रावधान द्वारा शासित होता है अर्थात जहां यह एक अन्याय के आधार पर एक वैधानिक अनुबंध पूरी तरह से है अलग-अलग। इस दृष्टिकोण से देखने पर हमारा मानना है कि नियमों के नियम 5 (15) को खत्म नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी द्वारा आग्रह किए गए और एक सांविधिक अनुबंध को निष्पक्षता के सिद्धांत का आयात करके बदला, जोड़ा या बदला नहीं जा सकता है। वर्तमान प्रकृति के अनुबंध में, लाइसेंसधारी एक लेता है परिकलित जोखिम। शायद अपीलार्थी पर्याप्त बुद्धिमान नहीं था लेकिन कानून में, उसे किए गए दायित्वों से मुक्त नहीं किया जा सकता है अनुबंध के तहत उसके द्वारा। इसाक पीटर (ऊपर) इसका समर्थन करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में इतनी स्पष्ट रूप से देखें और कहेंः

> "26 .....संक्षेप में, निष्पक्ष रूप से कार्य करने का कर्तव्य अनुबन्ध में होना चाहिए ना कि अपनी शर्तों को संशोधित करने और बदलने के लिए अनुबंध में आयात किया जाना चाहिए जिससे कि राज्य पर एक दायित्व पैदा किया जा सके। हम यह स्वीकार करते हैं कि हमें ऐसे किसी निष्पक्षता या तर्कसंगतता के सिद्धांत की जानकारी नहीं है। न ही विद्वान वकील इस तरह के एक प्रस्ताव नीचे किसी भी निर्णय को हमारे ध्यान में ला सके। निष्पक्षता या कर्तव्य का सिद्धांत निष्पक्ष और यथोचित रूप से कार्य

करना एक सिद्धांत है जिसमें विकसित किया गया है कानून का शासन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक कानून क्षेत्र और न्याय की विफलता को रोकें जहां कार्रवाई प्रशासनिक है निर्णय जहाँ कार्य अर्ध है- न्यायिक, सिद्धांत निष्पक्षता का विकास निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए किया गया है जहां कार्य प्रशासनिक है। लेकिन निश्चित रूप से ऐसा नहीं हो सकता है। पक्षों के बीच अनुबंध में व्यक्त शर्तों में संशोधन, परिवर्तन या परिवर्तन करने के लिए आह्वान किया गया। यह ऐसा है, भले ही अनुबंध वैधानिक प्रावधानों द्वारा शासित है, अर्थात, जहाँ यह एक वैधानिक अनुबंध-या उससे भी अधिक। यह कहना एक बात है कि एक अनुबंध-प्रत्येक अनुबंध-का अर्थ लगाया जाना चाहिए। उचित रूप से अपनी भाषा को ध्यान में रखते हुए"।

19. अब अगर इस कोर्ट के निर्णय ब्रोजो नाथ गांगुली (ऊपर) जो कि सेवा की शर्तों से संबंधित है व इस कोर्ट द्वारा डी.सी. मजदूर कांग्रेस (ऊपर) के निर्णय में मंजूर किया गया है। लेकिन ऐसा करते हुए संविधान पीठ ने स्पष्ट रूप से स्पष्ट शब्दों में यह प्रतिपादित किया है कि तर्क संगतता या निष्पक्षता का सिद्धान्त वित्तीय लेन-देन पर लागू नहीं हो सकता है। हमारे लिए यह संभव नहीं है कि हम रोजगार के अनुबंध की तुलना विक्रेता रैक के अनुबंध से करें। रोजगार का अनुबंध और एक

व्यापारिक लेन-देन एक अलग आधार पर होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जब विक्रेता रैक का अनुबंध किसी व्यक्ति के साथ है अथवा किसी राज्य के बीच होता है। यह निम्नलिखित निर्णय के व्याख्यान से स्पष्ट है।

"286.....हालाँकि, यह सिद्धांत लागू नहीं होगा जहाँ संविदाकारी पक्षों की सौदेबाजी की शक्ति बराबर है या लगभग बराबर या जहाँ दोनों पक्ष व्यवसायी हैं और अनुबंध एक वाणिज्यिक लेनदेन है।

(हमारा रेखांकित करना)

20. तदनुसार, हमारी राय में एक अनुबन्ध जो आबकारी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किया गया है, इसमें जो अनुज्ञप्तिधारी दी गई है उसमें इसके अन्तर्गत के नियमों और शर्तों का पालन करने का वचन दिया जाता है। इन परिस्थितियों में ऐसी अनुज्ञप्तिधारी तर्क संगतता या निष्पक्षता के सिद्धानत का आवाहान नहीं कर सकती। इसलिए, हम अपीलार्थी के तर्क को नकारते हैं।

21. परिणामस्वरूप, हम अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं और इसे तदनुसार खारिज किया जाता है परन्तु लागत के रूप में किसी भी आदेश के बिना।

आर.पी.

याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी वमीता सिंह (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।